

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	टॉपिक का नाम
1.	'वंदे गंगा' जल संरक्षण - जन अभियान, 2026
2.	'PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' में राजस्थान 5वें स्थान पर
3.	न्यूज़ इन शॉर्ट्स 1. राजस्थान का तीसरा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) 2. माउंट आबू ग्रीष्म महोत्सव - 2026 3. एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का पहला पुलिस थाना 4. रोबोटिक्स सर्जरी के लिए 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस' 5. राव दूदाजी की मूर्ति का अनावरण 6. पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोसिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण 7. बीकानेर से 'करियर काउंसलिंग वैन' का शुभारंभ
4.	100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता
5.	लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं का संवर्धन योजना
6.	भारतीय कृषि-निर्यात में रिकॉर्ड संवृद्धि
7.	विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)
8.	भारत में सोने और चांदी के आयात शुल्क में वृद्धि
9.	बहुसंख्यकवाद, संविधानवाद को दबा नहीं सकता: उच्चतम न्यायालय
10.	भारतीय जहाजरानी निर्माण क्षेत्रक
11.	भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग
12.	लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2025 रिपोर्ट



राजस्थान परिदृश्य



'वंदे गंगा' जल संरक्षण - जन अभियान, 2026

चर्चा में क्यों?

- 25 मई, 2026 (गंगा दशमी) से प्रदेश में भू-जल स्तर और जल संचयन में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से 'वंदे गंगा' जल संरक्षण - जन अभियान' का शुभारंभ किया जाएगा।

मुख्य बिन्दु:

- शुभारंभ** : जयपुर एक्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर (JECC), सीतापुरा से।
- आयोजन अवधि** : 25 मई से 05 जून, 2026 तक (गंगा दशमी से विश्व पर्यावरण दिवस तक)।
- अभियान के शुभारंभ समारोह में जल संरक्षण में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को 'जल गौरव सम्मान' से सम्मानित किया जाएगा।

अभियान के तहत विभागवार प्रमुख गतिविधियाँ :

विभाग	गतिविधियाँ
जल संसाधन विभाग	नदी, वृहद एवं मध्यम बाँध, सरोवर, नहरों की पूजा, जल शक्ति अभियान: कैच द रैन के अंतर्गत कार्यक्रम, जल संचयन जन भागीदारी कार्यक्रम आदि।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	'जल परीक्षण अभियान' का आयोजन।

Daily Current Affairs

Date : 15 May, 2026



उद्योग एवं वाणिज्य विभाग	औद्योगिक संस्थानों, निजी एवं राजकीय कार्यालयों को ग्रीन ऑफिस इनिशिएटिव, एनर्जी ऑडिट एवं ग्रीन बजट के संबंध में जानकारी।
स्वायत्त शासन विभाग	जल स्रोतों पर दीप प्रज्ज्वलन, महापुरुषों की प्रतिमाओं की साफ-सफाई, प्लास्टिक कचरे का चिह्नित स्थल पर निष्पादन, 'अमृत 2.0 योजना' के अंतर्गत नवीन कार्यदिश जारी।
कृषि एवं उद्यान विभाग	स्प्रिंकलर, ड्रिप, फार्म पौंड, पाइप लाइन की स्वीकृतियाँ जारी की जाएंगी। प्राकृतिक, जैविक, सूक्ष्म सिंचाई पद्धति पर कार्यशाला एवं प्रदर्शनियाँ।
वन एवं पर्यावरण विभाग	4 जून को 'रन फॉर एन्वायरमेंट' का आयोजन। 'हरियालो राजस्थान' की पूर्व तैयारियाँ।

अन्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु:

वर्ष 2025 का 'वन्दे गंगा' जल संरक्षण जन अभियान:

- आयोजन : 5 से 20 जून, 2025 तक।
- अभियान की शुरुआत : विश्व पर्यावरण दिवस व गंगा दशहरा (05 जून) के अवसर पर जयपुर के रामगढ़ बाँध से।
- समापन : जैसलमेर की गड़ीसर झील।

--3--

'PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' में राजस्थान 5वें स्थान पर



चर्चा में क्यों?

- 14 मई, 2026 तक राजस्थान में 'PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' के तहत 2 लाख रूपफ टॉप सौर ऊर्जा संयंत्र इंस्टॉल किए जा चुके हैं।



नवीन एवं
नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
MINISTRY OF
NEW AND
RENEWABLE ENERGY
समृद्धि कर्म

REPLACE ELECTRICITY BILL STRESS WITH SAVINGS!

Install Rooftop Solar with

PM SURYA GHAR: MUFT BIJLI YOJANA



Government
Subsidy
up to ₹ 78,000



Collateral
Free Loan
at 6.75%



Transparent
application and
swift processing

To know more visit pmsuryaghar.gov.in
or Download PM Surya Ghar app available on Android / ios

Please join our WhatsApp channel



:-4:-

Daily Current Affairs

Date : 15 May, 2026



मुख्य बिन्दु:

- दो लाख वाँ रूफ टॉप संयंत्र : जयपुर निवासी तारा शर्मा इस योजना के तहत दो लाख वाँ रूफ टॉप संयंत्र स्थापित करवाने वाली उपभोक्ता बनी।
- उल्लेखनीय है कि राज्य में अब तक इस योजना के अंतर्गत 771 मेगावाट (MW) क्षमता के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

योजना के तहत राजस्थान के शीर्ष - 5 जिले:

रैंक	ज़िला	इंस्टॉल किए गए संयंत्रों की संख्या
1 st	जयपुर	41,296
2 nd	श्री गंगानगर	19,135
3 rd	सीकर	12,104
4 th	हनुमानगढ़	11,530
5 th	झुंझुनूं	10,185

योजना के तहत देश के शीर्ष - 5 राज्य :

रैंक	राज्य	इंस्टॉल किए गए संयंत्रों की संख्या (लाख में)
1 st	गुजरात	6.61
2 nd	महाराष्ट्र	5.69
3 rd	उत्तर प्रदेश	5.25
4 th	केरल	2.39
5 th	राजस्थान	2.04

--:5:--

Daily Current Affairs

Date : 15 May, 2026



फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स:

पीएम सूर्य घर : मुफ्त बिजली योजना।

- **लॉन्च** : 13 फरवरी, 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
- **संबंधित मंत्रालय** : नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय।
- **उद्देश्य** : रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना की सुविधा के द्वारा घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करना।
- **लक्ष्य** : मार्च, 2027 तक एक करोड़ घरों में सौर ऊर्जा की आपूर्ति करना।
- राज्य सरकार ने अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए 'एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति-2024' जारी की है, जिसमें रूफटॉप सोलर को बढ़ावा देने के लिए नेट मीटरिंग, ग्रॉस मीटरिंग के साथ-साथ वर्चुअल नेट मीटरिंग एवं ग्रुप नेट मीटरिंग के प्रावधान किए गए हैं।

योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सब्सिडी:

औसत मासिक बिजली खपत (यूनिट)	उपयुक्त रूफटॉप सौर संयंत्र क्षमता	सब्सिडी सहायता
0-150	1-2 kW	₹30,000/- से ₹60,000/-
150-300	2-3 kW	₹60,000/- से ₹78,000/-
300 से अधिक	3 kW से ऊपर	₹78,000/-

--6--

✂ न्यूज़ इन शॉर्ट्स ⚡

क्र. सं.	न्यूज़
1.	<p>राजस्थान का तीसरा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP)</p> <ul style="list-style-type: none">■ जोधपुर के मथानिया में राजस्थान का तीसरा फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) स्थापित किया जाएगा।■ फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट (FSTP) सेप्टिक टैंकों से निकलने वाले मल को वैज्ञानिक तरीके से उपचारित करने वाली एक किफायती और टिकाऊ प्रणाली है।■ यह तकनीक ठोस मल को खाद में और तरल को उपचारित जल में बदलकर पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित करती है।■ यह विकेंद्रीकृत प्रणाली ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लिए आदर्श है, जहाँ सीवर लाइन नहीं है।
2.	<p>माउंट आबू ग्रीष्म महोत्सव - 2026</p> <ul style="list-style-type: none">■ आयोजन : राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन 'माउंट आबू' में 9 और 10 मई, 2026 को।■ आयोजक : राजस्थान पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन सिरोही।■ मुख्य आकर्षण : बॉलीवुड की प्रसिद्ध पार्श्व गायिका तुलसी कुमार की लाइव प्रस्तुति और 'ड्यून ऑफ राजस्थान' बैंड का सूफियाना संगीत।
3.	<p>एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का पहला पुलिस थाना</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) का पहला पुलिस थाना जयपुर में खोला गया।■ इस विशेष पुलिस थाने का उद्घाटन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के ADG दिनेश एम.एन. द्वारा किया गया।■ राज्य स्तर पर जयपुर का यह थाना समूचे राजस्थान में ANTF के ऑपरेशनों को मॉनिटर और संचालन करता है।■ वर्तमान में पूरे राज्य में नशे की तस्करी रोकने के लिए 18 विशेष चौकियाँ और एक पुलिस थाना सक्रिय हैं।

4.	<p>रोबोटिक्स सर्जरी के लिए 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस'</p> <ul style="list-style-type: none">■ अजमेर स्थित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय (JLNH) को रोबोटिक्स सर्जरी के लिए 'सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस (CoE)' के रूप में विकसित किया जाएगा।■ अस्पताल के विकास कार्यों एवं चिकित्सा सेवाओं के सुदृढीकरण के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष (CMRF) से सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।■ राजस्थान मुख्यमंत्री सहायता कोष (CMRF) राज्य के निर्धन और जरूरतमंद नागरिकों को गंभीर बीमारियों के इलाज, दुर्घटना सहायता और प्राकृतिक आपदाओं में आर्थिक सहायता प्रदान करता है।■ यह कोष मुख्य रूप से 2 लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले नॉन-बीपीएल परिवारों को कैंसर, हृदय और गुर्दा रोगों के इलाज के लिए सहायता देता है।
5.	<p>राव दूदाजी की मूर्ति का अनावरण</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नागौर के मेड़ता में राव दूदाजी की मूर्ति का अनावरण किया गया।■ राव दूदा जी (1440-1515 ई.) जोधपुर के संस्थापक राव जोधा के चौथे पुत्र और मेड़तिया राठौड़ वंश के संस्थापक शासक थे।■ वे संत मीरा बाई के दादाजी थे और मेड़ता क्षेत्र को स्वतंत्र कर एक अन्य राठौड़ साम्राज्य की नींव रखी।
6.	<p>पूर्व उपराष्ट्रपति स्व. भैरोसिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरोसिंह शेखावत (बाबोसा) की प्रतिमा का अनावरण किया गया।■ अनावरण स्थल : जोधपुर।
7.	<p>बीकानेर से 'करियर काउंसलिंग वैन' का शुभारंभ</p> <ul style="list-style-type: none">■ हाल ही में, केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बीकानेर में निर्विकल्प फाउंडेशन द्वारा बीकाजी के सहयोग से संचालित होने वाले करियर काउंसलिंग वैन का शुभारंभ किया।■ यह वैन बीकाजी के संस्थापक शिवरतन अग्रवाल (फन्ना बाबू) को समर्पित की गई है।

आर्थिक घटनाक्रम

100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता

चर्चा में क्यों?

- TERI ने एक रिपोर्ट में भारत द्वारा 2047 तक 100 GW परमाणु ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य प्राप्त करने का रोडमैप बताया गया है।



मुख्य बिन्दु:

- वर्तमान में, देश में सात स्थलों पर 25 परमाणु रिएक्टर्स संचालित हैं। इनकी कुल परमाणु ऊर्जा स्थापित क्षमता 8.8 गीगावाट (GW) है।
- क्षमता विस्तार:** बड़े दाबित भारी जल रिएक्टर्स (PHWRs) को निरंतर और स्थिर बिजली आपूर्ति (बेस लोड पावर) का मुख्य आधार बनाना होगा। वहीं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स (SMRs) का उपयोग इस्पात और सीमेंट जैसे उन क्षेत्रों में किया जाएगा जहाँ कार्बन उत्सर्जन कम करना कठिन है।

- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लघु रूप हैं। ये रिएक्टर्स प्रति मॉड्यूल 300 मेगावाट तक विद्युत उत्पन्न करते हैं। इन रिएक्टर्स के निम्नलिखित लाभ हैं -
- **मॉड्यूलर संरचना:** कारखानों में बने हिस्सों के कारण इन्हें शीघ्र जोड़ा जा सकता है और लागत कम होती है।
- **क्षमता विस्तार की सुविधा:** ऊर्जा की बढ़ती माँग के अनुसार इनकी क्षमता चरणबद्ध तरीके से बढ़ाई जा सकती है।
- **बेहतर सुरक्षा:** इनमें पैसिव सुरक्षा प्रणाली होती है, जिससे किसी आपात स्थिति में इंसानों के बिना हस्तक्षेप के स्वतः शटडाउन संभव होता है।
- **बड़े पैमाने पर निवेश जुटाने की आवश्यकता:** परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए लगभग ₹23-25 लाख करोड़ के अनुमानित पूँजीगत व्यय की आवश्यकता होगी।
- **कार्यबल का विस्तार:** केवल निर्माण चरण में ही 1.2-2 लाख कर्मियों की आवश्यकता होगी, जिसके लिए विशेष कौशल प्रशिक्षण में बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के उपयोग और निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए वर्तमान विनियामक व्यवस्था पुरानी पड़ चुकी है।
- शांति अधिनियम (2025) में ऐसे रिएक्टर्स के परिचालन पर स्पष्ट नियमों, परियोजना के स्वामित्व और निजी क्षेत्र की भागीदारी पर वित्तीय मॉडल पर स्पष्टता का अभाव है।
- उच्च पूँजीगत लागत (₹20-25 करोड़ प्रति मेगावाट), परमाणु ईंधन के लिए आयात पर अधिक निर्भरता और परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर भी समस्याएँ हैं।
- विशिष्ट कौशल वाले कर्मियों की कमी है। लोगों के मन में परमाणु ऊर्जा के खतरों को लेकर अभी भी आशंकाएँ विद्यमान हैं।

लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं का संवर्धन योजना

चर्चा में क्यों?

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं का संवर्धन योजना' को मंजूरी दी।



मुख्य बिन्दु:

- यह योजना राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन, 2021 के तहत वर्ष 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयले के गैसीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी।
- कोयला गैसीकरण वास्तव में एक प्रकार की ऊष्मा-रासायनिक (thermochemical) प्रक्रिया है, जिसमें कोयले को सिंथेसिस गैस (सिनगैस) नामक बहुउपयोगी और ज्वलनशील गैसीय मिश्रण में परिवर्तित किया जाता है।
- सिनगैस कार्बन मोनोऑक्साइड (CO) और हाइड्रोजन (H₂) का मिश्रण है। इसका उपयोग यूरिया, मेथनॉल, सिंथेटिक प्राकृतिक गैस (SNG) और अमोनिया जैसे उत्पादों के निर्माण में किया जाता है।

Daily Current Affairs

Date : 15 May, 2026



- **भारत में कोयला/लिग्नाइट भंडार की स्थिति:** कोयला भंडार (401 बिलियन टन); लिग्नाइट भंडार (47 बिलियन टन)।

योजना की मुख्य विशेषताएँ

- **लक्ष्य:** घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान करके लगभग 75 मिलियन टन (MT) कोयले और लिग्नाइट का गैसीकरण करना।
- **वित्तीय प्रोत्साहन:** संयंत्र और मशीनरी की लागत का अधिकतम 20%, जो परियोजना की उपलब्धि चरणों से जुड़े चार किस्तों में वितरित किया जाएगा।
- **नीतिगत सहायता:** दीर्घकालिक निवेश प्रदान करने के लिए, सरकार ने 'गैर-विनियमित क्षेत्रक लिंकेज नीलामी फ्रेमवर्क' के तहत कोयला लिंकेज अवधि को बढ़ाकर 30 वर्ष तक कर दिया है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

-:12:-

भारतीय कृषि-निर्यात में रिकॉर्ड संवृद्धि

चर्चा में क्यों?

- संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा आरोपित उच्च टैरिफ दरों के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का कृषि निर्यात मूल्य तेजी से बढ़ते हुए 50 बिलियन डॉलर के पार पहुँच गया।



मुख्य बिन्दु:

भारत के कृषि-निर्यात में संवृद्धि के कारण:

- **बाजार का विविधीकरण:** उदाहरण के लिए, समुद्री उत्पादों के निर्यात में चीन, वियतनाम, जापान और बेल्जियम जैसे देशों में भेजे जाने वाले शिपमेंट में भारी वृद्धि दर्ज की गई।
- **वैश्विक गतिशील परिस्थितियाँ:** विश्व में कॉफी के सबसे बड़े उत्पादक देशों (ब्राजील और वियतनाम) में कम फसल पैदावार के कारण भारतीय निर्यात के लिए बड़ा और लाभकारी अवसर उत्पन्न हुए।
- **मूल्य संवर्धन:** कुल कृषि निर्यात में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात की हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है। यह हिस्सेदारी वित्तीय वर्ष 2018 की लगभग 15% से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2025 में लगभग 20% हो गई।

Daily Current Affairs

Date : 15 May, 2026



कृषि-निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सरकारी पहलें:

- **कृषि निर्यात नीति 2018 (AEP):** यह नीति कृषि-निर्यात को दोगुना करने, निर्यात उत्पादों में विविधता लाने तथा स्वदेशी, ऑर्गेनिक एवं पारंपरिक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई है।
- **कृषि उड़ान योजना 2.0:** यह योजना शीघ्र खराब होने वाले कृषि-उत्पादों को बाजार तक तुरंत पहुँचाने के लिए वायु-परिवहन की सुविधा प्रदान करती है, विशेष रूप से पूर्वोत्तर और जनजातीय क्षेत्रों के उत्पादों के लिए।
- **एक जिला एक निर्यात हब पहल:** स्थानीय वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' (ODOP) के तहत प्रत्येक जिले से निर्यात क्षमता वाले विशिष्ट उत्पादों की पहचान की जाती है।

UTKARSH

CIVIL
SERVICES

--:14:--

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)

चर्चा में क्यों?

- केंद्र सरकार ने सितंबर, 2026 तक चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि इसकी घरेलू कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके।

Directorate General of Foreign Trade



मुख्य बिन्दु:

- विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने निर्यात नीति को 'निषिद्ध' (Restricted) से बदलकर 'प्रतिबंधित' (Prohibited) कर दिया है।

विदेश व्यापार महानिदेशालय

- **संबंधित मंत्रालय:** केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत एक संबद्ध कार्यालय।
- **कार्य:** भारत की विदेश व्यापार नीति तैयार करना और उसे लागू करना।
- **भूमिका:** देश के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्यात/ आयात को बढ़ावा देना और सुगम बनाना।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली और पूरे भारत में 24 क्षेत्रीय कार्यालय।

भारत में सोने और चांदी के आयात शुल्क में वृद्धि

चर्चा में क्यों?

- भारत सरकार ने सोने और चांदी पर प्रभावी आयात कर को 9.2% से बढ़ाकर 18.4% कर दिया है।



मुख्य बिन्दु:

- सीमा शुल्क 5% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया, जबकि कृषि अवसंरचना और विकास उपकर (AIDC) 1% से बढ़कर 5% हो गया।

नवीनतम निर्णय के पीछे का कारण

- यह निर्णय प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से रुपये और विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा में मदद करने के लिए अस्थायी रूप से सोने की खरीद कम करने के आग्रह के तुरंत बाद आया।

- सरकार ने इस कदम को चिंताओं से जोड़ा है।
 - चालू खाता घाटा (सीए) में वृद्धि
 - विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव
 - पश्चिम एशिया संकट के कारण वैश्विक अनिश्चितता
 - कच्चे तेल की कीमतों और शिपिंग मार्गों में अस्थिरता।
 - कच्चे तेल, उर्वरक, रक्षा उपकरण और औद्योगिक सामान जैसे आवश्यक आयात के लिए विदेशी मुद्रा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
- महत्त्वपूर्ण पद**
- **चालू खाता घाटा (सीए):** सीए वह अंतर है जिससे किसी देश का वस्तुओं, सेवाओं और हस्तांतरणों का कुल आयात उसके निर्यात से अधिक होता है।
 - कृषि अवसंरचना एवं विकास उपकरण को केंद्रीय बजट 2021-22 में कुछ वस्तुओं, जिनमें कृषि उत्पाद और संबंधित वस्तुएं शामिल हैं, पर निर्दिष्ट दरों पर लगाए जाने वाले कर के रूप में पेश किया गया था।
 - इसका मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि अवसंरचना के विकास और सुधार के लिए धन जुटाना है।
 - यह उपकरण सोना, चांदी, मादक पेय पदार्थ, कच्चे खाद्य तेल, सेब, कोयला, उर्वरक, दालें और कपास जैसे उत्पादों पर लागू होता है।
 - **आयात शुल्क :** यह किसी देश के सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा आयात और कुछ निर्यातों पर वसूला जाने वाला कर है।

भारतीय शासन एवं राजव्यवस्था

बहुसंख्यकवाद, संविधानवाद को दबा नहीं सकता: उच्चतम न्यायालय

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की कि भारत एक संवैधानिक लोकतंत्र है, जहाँ बहुमत का शासन चलता है, लेकिन न्यायालयों का यह कर्तव्य है कि वे सरकार या बहुमत के निर्णयों को संविधान के सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर परखें।

मुख्य बिन्दु:

- उपर्युक्त टिप्पणी "धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार" के विस्तार की समीक्षा कर रही नौ न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा की गई।

संविधानवाद (Constitutionalism)

- इसका तात्पर्य एक ऐसी व्यवस्था से है जिसमें सरकार की शक्तियाँ संविधान द्वारा सीमित होती हैं।

महत्त्व:

- अधिकारों की रक्षा:** यह राज्य के हस्तक्षेप से मूलभूत स्वतंत्रताओं की रक्षा करता है।
- विधि के शासन का संरक्षण:** यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को निष्पक्ष और स्थिर कानूनों का संरक्षण प्राप्त हो। जैसे- अनुच्छेद 14 के तहत 'विधि के समक्ष समता का अधिकार'।
- लोकतंत्र की रक्षा:** यह निष्पक्ष चुनावों की गारंटी देता है और सुनिश्चित करता है कि सत्ता जनता में निहित रहे।
- जवाबदेही सुनिश्चित:** सरकार के कामकाज को पारदर्शी बनाए रखने के लिए CAG जैसी संस्थाओं के माध्यम से स्वतंत्र निगरानी करता है।

- **शक्तियों का पृथक्करण:** सरकार की शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित किया जाता है, ताकि कोई एक संस्था अत्यधिक शक्तिशाली न बन सके।
- **बहुसंख्यकवाद को नियंत्रित:** यह सुनिश्चित करता है कि बहुमत का शासन अल्पसंख्यक और कमजोर वर्गों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। उदाहरण- संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 भाषाई तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

संविधानवाद के समक्ष चुनौतियाँ

- सत्तावादी प्रवृत्तियों का बढ़ना, जो संवैधानिक सिद्धांतों को कमजोर करता है।
- न्यायिक अतिक्रमण, जो शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को चुनौती देता है।
- शासन संबंधी समस्याएं (जैसे- भ्रष्टाचार), जो लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को कम कर सकती हैं।

संविधानवाद से संबंधित प्रमुख न्यायिक निर्णय:

- **केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) वाद:** इसमें मूल संरचना के सिद्धांत की अवधारणा सामने आई। न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संविधान संशोधन संविधान के मूल सिद्धांतों को नहीं बदल सकते।
- **रामेश्वर प्रसाद बनाम भारत संघ (2006) वाद:** न्यायालय ने कहा कि संविधानवाद विधि के शासन पर आधारित है, और यह निरंकुशता को खारिज करती है।
- **आई.आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) वाद:** इसमें कहा गया कि संविधानवाद के सिद्धांत की रक्षा के लिए सरकार की शक्ति पर नियंत्रण आवश्यक है ताकि लोकतांत्रिक सिद्धांत कमजोर न हों।

अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य

भारतीय जहाजरानी निर्माण क्षेत्रक

चर्चा में क्यों?

- भारत-कोरिया गणराज्य व्यापक ढांचे 'VOYAGES' के तहत तमिलनाडु के थूथुकुडी में भारत के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड को विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।



मुख्य बिन्दु:

'VOYAGES'

- VOYAGES से आशय है; शेयर्ड विज़न फॉर ऑपरेशन ऑफ यार्ड असिस्टेड ग्रोथ विद एफिशिएंसी एंड स्केल।

--:20:--

Daily Current Affairs

Date : 15 May, 2026



- अप्रैल 2026 में हस्ताक्षरित, यह समझौता प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, हरित जहाज निर्माण और दक्षिण कोरिया में भारतीय पेशेवरों के प्रशिक्षण के माध्यम से जहाज निर्माण, शिपिंग और समुद्री लॉजिस्टिक्स में भारत-दक्षिण कोरिया सहयोग को बढ़ावा देता है।

भारत के जहाज निर्माण क्षेत्र का अवलोकन

- **वैश्विक स्थिति:** जहाज निर्माण क्षेत्र में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 1% से भी कम है, जो चीन (47%), दक्षिण कोरिया (25%) और जापान (18%) से काफी पीछे है।
- **पुराने बेड़े:** भारतीय फ्लीट्स की औसत आयु 21 वर्ष है, जिससे लगभग 2,500 नए जहाजों की मांग उत्पन्न हो रही है।
- **बाजार में वृद्धि:** इस क्षेत्र के 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर (2022) से बढ़कर 2033 तक 8.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।



--:21:--

भारत-श्रीलंका आर्थिक सहयोग

चर्चा में क्यों?

- मुंबई में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा सीलोन चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ साझेदारी में आयोजित भारत-श्रीलंका व्यापार मंच ने छह प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की।



मुख्य बिन्दु:

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **बंदरगाह:** भारत और श्रीलंका व्यापार और क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए बंदरगाह अवसंरचना और समुद्री संपर्क में सहयोग की संभावनाओं का पता लगा रहे हैं।
- **परिवहन और रसद:** रसद दक्षता बढ़ाने के लिए शिपिंग मार्गों, रेल संपर्क, भंडारण और शीत भंडारण सुविधाओं में सुधार करना।
- **दवाइयाँ:** श्रीलंका ने मौजूदा मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) ढांचे के तहत भारत से सस्ती जेनेरिक दवाओं के आयात में रुचि दिखाई है।
- **डिजिटल भुगतान:** श्रीलंका भारत के साथ यूपीआई जैसी सीमा पार डिजिटल भुगतान प्रणालियों की संभावनाओं का पता लगा रहा है।

--:22:--

- **यात्रा और पर्यटन:** बेहतर वीजा सुविधाओं और यात्रा मार्गों के माध्यम से पर्यटन और यात्रा संपर्क का विस्तार करना।
- **भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) की समीक्षा:** दोनों देश एफटीए को अद्यतन करने पर विचार कर रहे हैं ताकि इसमें दवाइयों से संबंधित कच्चे माल, लॉजिस्टिक्स उपकरण और व्यापार सुविधा उपायों को शामिल किया जा सके।

द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग में चुनौतियाँ

- **व्यापार असंतुलन:** श्रीलंका को भारत के साथ व्यापार घाटे को लेकर चिंता है।
- **नियामक बाधाएँ:** सीमा शुल्क निकासी और नियामक अनुमोदनों में देरी व्यापार दक्षता को प्रभावित करती है।
- **बुनियादी ढाँचे की बाधाएँ:** सीमित रसद और परिवहन बुनियादी ढाँचे के कारण व्यापार लागत बढ़ सकती है।
- **आर्थिक अस्थिरता:** श्रीलंका के हालिया आर्थिक संकट ने निवेशकों के विश्वास को प्रभावित किया है।
- **भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा:** बाहरी शक्तियाँ बंदरगाहों और बुनियादी ढाँचे जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में प्रभाव हासिल करने के लिए तेजी से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं।

भारत के लिए श्रीलंका का महत्त्व

- **रणनीतिक स्थिति:** श्रीलंका हिंद महासागर में संचार के महत्त्वपूर्ण समुद्री मार्गों के निकट स्थित है, जिनसे होकर भारत की 60% से अधिक ऊर्जा आपूर्ति और महत्त्वपूर्ण व्यापार गुजरता है।
- **समुद्री सुरक्षा:** क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने और चीन की नौसैनिक उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए भारत की सागर पहल के तहत यह अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

महत्त्वपूर्ण सूचकांक एवं रिपोर्ट

लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2025 रिपोर्ट



चर्चा में क्यों?

- लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स (LEADS) 2025 रिपोर्ट जारी की गई। वर्ष 2025 की रिपोर्ट LEADS का सातवां संस्करण है।

LOGISTICS EASE ACROSS DIFFERENT STATES (LEADS) 2025



मुख्य बिन्दु:

- LEADS राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में प्रदर्शन का मूल्यांकन करने वाली एक प्रमुख रिपोर्ट है। इसे भारत सरकार के उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) द्वारा जारी किया जाता है।

LEADS रिपोर्ट

- शुरुआत:** इसे 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) की तर्ज पर तैयार किया गया था।
- नया ढांचा:** LEADS 2025 में अब चार-स्तरीय प्रदर्शन ढांचा शामिल किया गया है। पहले की रिपोर्टों में त्रिस्तरीय प्रदर्शन मानदंड अपनाया गया था।
- मूल्यांकन के संकेतक:** इसमें वस्तुनिष्ठ संकेतकों को लगभग 59% भारांश दिया गया है। जैसे कि विनियामकीय सहायता और लॉजिस्टिक्स सुविधाएँ।

Daily Current Affairs

Date : 15 May, 2026



- साथ ही, धारणा आधारित संकेतकों को भी शामिल किया गया है, जैसे— लॉजिस्टिक्स अवसंरचना, सेवाएँ और सतत लॉजिस्टिक्स।

भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक की वर्तमान स्थिति और चुनौतियां

- **लॉजिस्टिक्स लागत:** वित्तीय वर्ष 2023-2024 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में लॉजिस्टिक्स लागत GDP का लगभग 8% है।

प्रमुख चुनौतियां:

- **अवसंरचना की कमियाँ:** खराब सड़कें, बंदरगाहों पर अधिक यातायात और सभी जगह रेल संपर्क नहीं होना।
- **परिवहन के लिए सड़क मार्ग पर अधिक निर्भरता:** भारत में 60% से अधिक माल ढुलाई सड़कों के माध्यम से होती है। इससे ईंधन की खपत, ट्रैफिक जाम और परिवहन लागत में बढ़ोतरी होती है।
- **असंगठित क्षेत्र:** लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक में छोटे ऑपरेटरों का दबदबा है, जिससे परिचालन में अक्षमता उत्पन्न होती है।
- **अन्य चुनौतियाँ:** जटिल विनियामक प्रक्रियाएँ और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को अपनाने की धीमी गति।

लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को सुदृढ़ करने के लिए प्रमुख पहलें

- **राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (NLP) 2022:** इसका लक्ष्य लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करके अन्य विकसित देशों के बराबर लाना है।
- **पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान:** यह एकीकृत अवसंरचना मास्टर प्लान है, जिसका उद्देश्य लोगों और वस्तुओं की निर्बाध तथा तेज आवाजाही सुनिश्चित करना है।
- **लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक 2.0:** यह यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म (ULIP) की APIs (अप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफ़ेस) के साथ समन्वय करता है। इससे निर्यातकों और MSMEs को सड़क, रेल, समुद्र आदि के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन की रियल-टाइम जानकारी और ट्रैकिंग सुविधा मिलती है।
- **अन्य पहलें:** समर्पित मालभाड़ा गलियारा (DFCs) परियोजनाएँ, मल्टीमॉडल और एकीकृत लॉजिस्टिक्स प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्यक्रम (SMILE), मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (MMLP), ई-वे बिल सिस्टम, लॉजिस्टिक्स क्षेत्रक को अवसंरचना का दर्जा, लॉजिस्टिक्स दक्षता संवर्धन कार्यक्रम, आदि।

--:25:--